SOUTHERN RAILWAY

No.P(R)MC-46/Increments

Headquarters Office
Personnel Branch
Chennai- 600 003
Dated: 15-02-2013

RBE No. 6/2013 **S.No. PC-VI/312** **PBC No:10 / 2013**

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs / DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Wokshops / other Units, etc.,
(As per mailing list –'A')

Sub: Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 – The re-exercise of option under Rule 6 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 in the case of employees covered under letter dated 23-03-2012.

***

A copy Railway Board's letter No.PC-VI/2012/I/RSRP/1 dated 28-01-2013 on the above subject is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Railway Board's letter dated 23-03-2012 referred therein has been circulated under PBC No. 49 / 2012 dt. 03-04-2012.

(M.SRINIVASALU) 15/2/13
Asst.Personnel Officer / Rules
for Chief Personnel Officer

Encl: as above

Copy to : The Genl.Secy. SRMU
The Genl.Secy. DREU
The Genl.Secy. AISCSTREA
The Genl.Secy. AIOBCREA

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(Railway Board)
*****

S.No.PC-VI/ 312 **RBE No.06 /2013**

No.PC-VI/2012/I/RSRP/1 **New Delhi, dated 28.01.2013**

The GMs/CAOs(R),
All Indian Railways & Production Units
(As per mailing list)

Sub: Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 – The re-exercise of option under Rule 6 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 in the case of employees covered under letter dated 23.03.2012.

As per provisions contained in Rules 5 & 6 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008, the railway employee had an option to elect to come over to the revised pay structure either from 01.01.2006 or from the date of his next increment or from the date of promotion, upgradation of pay scales. Such an option was to be exercised within 3 months from the date of publication of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008. The rule also provides that the option once exercised shall be final.

2. This Ministry issued instructions vide letter of even No dated 23.03.2012 providing that those Railway employees who were due to get their annual increment between February, 2006 to June, 2006 may be granted one increment on 01.01.2006 in the pre-revised pay scale as a onetime measure and, thereafter, they will get the next increment in the Revised Pay structure on 01.7.2006 as per Rule 10 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008.

3. In view of the benefit extended to the employees as per the aforesaid letter dated 23.03.2012 the issue relating to according of a fresh opportunity to the employees to re-exercise their option to come over to the revised pay scale as per Revised Pay Rules, 2008 was raised by the Staff Side of the Joint Consultative Machinery in the meeting of the National Anomaly Committee held on 17.7.2012.

4. The matter has been considered by the Government and having regard to the fact that the provisions of the aforesaid letter dated 23.03.2012 bring about a material change in the basis for exercise of option to come over to the revised pay structure in terms of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 in respect of employees who are covered under the said letter dated 23.03.2012, the President is pleased to decide that all those employees who are covered under the provisions of aforesaid letter dated 23.03.2012 may once again be permitted to re-exercise their option to come over to the Revised Pay Structure.

...2/-

5. The benefit under these orders for re-exercise of option shall be available for a period upto 31.03.2013. The revised option shall be intimated to the head of the office by the concerned employees in accordance with the provision of Rule 6(2) of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008.

6. All the Zonal Railways/Production Units etc. are requested to bring the content of this letter to the notice of their employees so that such employees can avail themselves of the same within the stipulated time period.

7. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(M.K. PANDA)
Joint Director, Pay Commission
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र.सं. पीसी-VI / 312 आरबीई सं. 06 /2013

सं. पीसी-VI/2012/आई/आरएसआरपी/1 नई दिल्ली, 28.01.2013

महाप्रबंधक / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां.
(डाक सूची के अनुसार)

विषय: रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2008 – दिनांक 23.03.2012 के पत्र के तहत आने वाले कर्मचारियों के मामलों में रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 6 के अंतर्गत विकल्प का पुन: प्रयोग ।

रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियमों 5 और 6 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार रेलवे कर्मचारी के पास संशोधित वेतन संरचना को 01.01.2006 से या अपनी अगली वेतनवृद्धि की तारीख से या पदोन्नति, वेतनमान के अपग्रेडेशन की तारीख से अपनाने का विकल्प था । ऐसा विकल्प रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के प्रकाशन की तारीख से 3 माह के भीतर दिया जाना था। इस नियम में यह प्रावधान है कि एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

2. इस मंत्रालय ने दिनांक 23.03.2012 के समसंख्यक पत्र के तहत अनुदेश जारी किए जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि उन रेल कर्मचारियों, जिन्हें वार्षिक वेतनवृद्धि फरवरी, 2006 से जून, 2006 के बीच दी जानी थी, को एकबारगी उपाय के रूप में संशोधन-पूर्व के वेतनमान में 01.01.2006 को एक वेतनवृद्धि दी जाए और तत्पश्चात् उन्हें रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 10 के अनुसार 01.07.2006 को संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि दी जाएगी।

3. दिनांक 23.03.2012 के उक्त पत्र के अनुसार कर्मचारियों को दिए गए लाभ को देखते हुए संशोधित वेतन नियम, 2008 के अनुसार संशोधित वेतनमान पर कर्मचारियों को पुन: विकल्प देने का पुन: अवसर प्रदान करने से संबंधित मुद्दा, संयुक्त परामर्श तंत्र में कर्मचारी पक्ष द्वारा 17.07.2012 को आयोजित राष्ट्रीय विसंगति समिति की बैठक में उठाया गया था।

4. सरकार ने मामले पर विचार किया है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दिनांक 23.03.2012 के उक्त पत्र से दिनांक 23.03.2012 के उक्त पत्र के तहत आने वाले कर्मचारियों के संबंध में रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के विकल्प के प्रयोग के आधार पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, राष्ट्रपति जी ने सहर्ष विनिश्चय किया है कि दिनांक 23.03.2012 के उक्त पत्र के प्रावधानों के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों को

संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के अपने विकल्प का पुन: प्रयोग करने की अनुमति दी जाए।

5. इन आदेशों के तहत पुन: विकल्प देने का लाभ 31.03.2013 तक उपलब्ध रहेगा । रेल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 6(2) के उपबंधों के अनुसार संबंधित कर्मचारी द्वारा संशोधित विकल्प की सूचना कार्यालयाध्यक्ष को दी जाएगी ।

6. सभी क्षेत्रीय रेलों / उत्पादन इकाइयों आदि से अनुरोध है कि वे इस पत्र की विषय-वस्तु को अपने कर्मचारियों के ध्यान में लाएं ताकि ऐसे कर्मचारी निश्चित समयावधि के भीतर इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

7. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(एम0के0 पण्डा)
सं0 निदेशक, वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड